मुख्यमंत्री भजनलाल ने ''इमरजैंसी डायरी'' का विमोचन किया

जयपुर27 जून । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को ''द इमरजेंसी डायरी, वो वर्ष जिन्होंने एक नेता को गढ़ा'' पुस्तक का राजस्थान में विमोचन किया। यह पुस्तक ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित की गई है, जो देश के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे अंधकारमय कालखंड - आपातकाल - में युवा नरेन्द्र मोदी के संघर्षों और नेतृत्व क्षमता के उदय को रेखांकित करती है।

मुख्यमंत्री कार्यालय में पुस्तक का विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री

- **मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुस्तक में उस दौर के असली नायकों की जीवंत झलक प्रस्तुत की गई है।**

भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह पुस्तक न सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों का संग्रह है, बल्कि उस दौर के असली नायकों की जीवंत झलक भी प्रस्तुत करती है। पुस्तक में उन लोगों की प्रत्यक्ष कथाएं शामिल हैं, जिन्होंने आपातकाल के दौरान नरेन्द्र मोदी के साथ कार्य किया और उनके साहस, संगठन क्षमता और दूरदृष्टि को करीब से देखा। इसके साथ ही, इसमें दुर्लभ ऐतिहासिक दस्तावेज और अभिलेखीय सामग्री का भी समावेश किया गया है, जो इस पुस्तक और अधिक प्रामाणिक बनाते हैं।

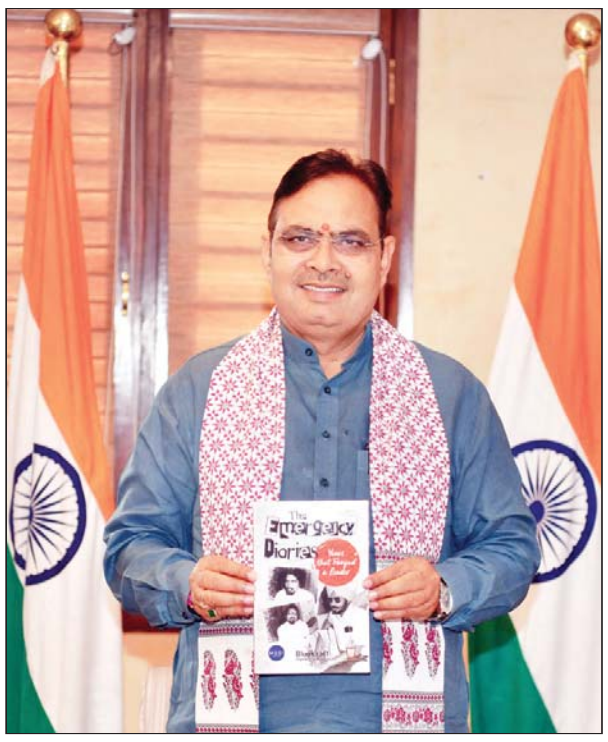

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को ''द इमरजेंसी डायरी, वो वर्ष जिन्होंने एक नेता को गढ़ा'' पुस्तक का विमोचन किया।

उन्होंने कहा कि यह पुस्तक विशेष रूप से युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, जो जान सकेंगे कि कैसे लोकतंत्र के संकट काल में भी कुछ नेता अडिग रहे और राष्ट्रिहत को सर्वोपरि रखा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लेखक, संपादक एवं प्रकाशक को इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए बधाई दी और आशा जताई कि यह कृति देशभर में जागरूकता फैलाने का कार्य करेगी।

मुख्यमंत्री ने रबी में नुकसान पर 239 करोड़ रूपए स्वीकृत किए

जयपुर, 27 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कृषि एवं कृषक- हित में निरंतर निर्णय ले रही है। किसानों का जीवनस्तर और बेहतर करने तथा उनकी आय में वृद्धि के लिए, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, गेंहू की एमएसपी खरीद पर अतिरिक्त बोनस, अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋण तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम

- **प्रदेश के 8 जिलों के 143 गाँवों में 20 हजार किसानों को रबी के दौरान ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए आदान-अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई है।**

वितरण जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने इसी क्रम में, प्रदेश के 143 गांवों के 70 हजार 366 किसानों को बड़ी राहत देते हुए 239 करोड़ रूपये के आदान-अनुदान की स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि आपदा राहत कोष से वितरित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि रबी फसल सीजन 2024-25 में प्रदेश के 8 जिलों की 18 तहसीलों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए इनकी त्वरित गिरदावरी करवाने के निर्देश दिए थे, जिसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा 33 प्रतिशत से अधिक खराबे वाले 143 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया था।

जुलाई के पहले सप्ताह में विदेश यात्रा पर जाएंगे प्र.मंत्री मोदी

प्रधानमंत्री 8 दिन में पांच देशों की यात्रा करेंगे

नयी दिल्ली, 27 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो से नौ जुलाई तक पांच देशों -घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना,ब्राजील तथा नामीबिया की आठ दिन की यात्रा पर जायेंगे। यह प्रधानमंत्री की घाना की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। वह ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।

भारतीय प्रधानमंत्री की घाना यात्रा तीन दशकों के बाद हो रही है। यात्रा के दौरान मोदी घाना के राष्ट्रपति के साथ मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा और आर्थिक, ऊर्जा, रक्षा तथा विकास सहयोग को साझेदारी के माध्यम से और बढ़ाने के लिए आगे के अवसरों पर चर्चा करेंगे। यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और 'पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय' तथा अफ्रीकी संघ के साथ भारत की भागीदारी को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी।

यात्रा के दूसरे चरण में तीन से चार जुलाई तक प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर वहां जायेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में उनका इस देश का पहला दौरा होगा। यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू और प्रधानमंत्री महामहिम कमला परसाद-बिसेसर के साथ वार्ता करेंगे। वे भारत-त्रिनिदाद और टोबैगो संबंधों को और मजबूत

- **ये पांच देश हैं घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेन्टीना, ब्राज़ील व नामीबिया।**
- **ब्राज़ील में मोदी 17 वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे।**

करने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा वहां की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किये जाने की भी उम्मीद है।

मोदी, यात्रा के तीसरे चरण में चार से पांच जुलाई तक अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर वहां की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। मोदी, राष्ट्रपति माइली के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें सहयोग की समीक्षा की जाएगी और रक्षा, कृषि, खनन, तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, व्यापार और निवेश तथा लोगों के बीच संबंधों सहित, प्रमुख क्षेत्रों में भारत-अर्जेंटीना साझेदारी को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री यात्रा के चौथे चरण में ब्राजील के राष्ट्रपति महामहिम लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा के निमंत्रण पर 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील की यात्रा करेंगे। यह प्रधानमंत्री की ब्राजील की चौथी यात्रा होगी। ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। ब्राजील की राजकीय यात्रा के लिए प्रधानमंत्री ब्रासीलिया जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति लूला के साथ व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संपर्क सहित, आपसी हित के क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में मोदी नामीबिया के राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवा के निमंत्रण पर 09 जुलाई को नामीबिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगे।

गैंगस्टर की मां की गोलीमार कर हत्या, बॉडीगॉर्ड भी मारा गया

बटाला (पंजाब), 27 जून। पंजाब के बटाला में देर रात कादियां रोड पर स्थित एक बेकरी के पास गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां और उनके बॉडीगार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला गैंगवार से जोड़ा जा रहा है। दविंदर बंबीहा गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है।

आरोपी दो बाइकों पर आए थे। उन्होंने कार के बिल्कुल नजदीक जाकर गोली चलाई। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। गोली लगने से

- **घटना पंजाब की है और मृतका हरजीत कौर जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां है।**

घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, महिला की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों पर केस दर्ज कर लिया है।

लॉरेंस के विरोधी बंबीहा गैंग से जुड़े 3 गैंगस्टरों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ली है। इनमें 2 गैंगस्टर प्रभू दासुवाल और कौशल चौधरी हरियाणा के हैं।

पुलिस इस घटना को आपसी गैंगवार से जोड़कर देख रही है, क्योंकि जग्गू पंजाब में लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा है। कई विरोधी गैंग से उसका टकराव रहा है।

राजनाथ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने रुसी एस-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति पर भी चर्चा की, जो भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। इसके अलावा सु-30 एनकेएल लड़ाकू विमानों के उन्नयन और आवश्यक सैन्य उपकरणों की त्वरित आपूर्ति पर भी वार्ता हुई। भारत ने रुस से एस-400 प्रणाली की पाँच स्क्वाड्रन का ऑर्डर दिया था, जिनमें से तीन पहले ही सक्रिय हो चुकी हैं, जबकि शेष दो के 2026 तक मिलने की उम्मीद है।

चीन, अमेरिका को ''रेअर अर्थ''...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है।

यह अकेली धमकी ही चीन की तरफ से अमेरिका को कई तरह की रियायतें दिलवाने में कामयाब रही, जिसमें चीन से आने वाले उत्पादों पर व्यापक आयात शुल्क भी शामिल है।

लेकिन दूसरी ओर, चीन, भारत के लिए इन्हीं दुर्लभ खनिजों और मैग्नेट्स के निर्यात को लगातार सीमित कर रहा है। वास्तव में, चीन ने भारत को किए जाने वाले, दुर्लभ खनिजों से लेकर विशेष उर्वरकों तक, कई वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों पर असर पड़ सकता है।

चीन भारत को मुख्यत: एक बड़ा बाज़ार मानता है और इसमें अपनी पहुँच भी चाहता है, लेकिन भारत को अपनी निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी कच्चा माल देना नहीं चाहता। दोनों देशों के बीच यह एक सतत संघर्ष का विषय रहा है, क्योंकि उनके संबंध स्वाभाविक रूप से प्रतिद्वंदात्मक हैं। रणनीतिक रूप से चीन एशिया में अपने वर्चस्ववादी मंसूबों के लिए भारत को एक बड़ी चुनौती मानता है। सन् 2020 में गलवान घाटी की घटना के दौरान, चीन ने भारत के खिलाफ अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश की थी।

तथापि, वास्तविक नियंत्रण रेखा (लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल) पर भारत ने जिस तरह से सैन्य प्रतिक्रिया दी, उससे चीन की उस योजना को झटका लगा। अब चीन अन्य तरीकों से दबाव बनाकर अपनी स्थिति फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के लिए जरूरी इनपुट सप्लाई पर नियंत्रण शामिल है। चीन ने भारत को टनल बोरिंग मशीनें (टी.बी.एम.) तक देना बंद कर दिया है, जो देश की कई महत्त्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बेहद जरूरी हैं।

बताया जा रहा है कि इन मशीनों की देर से आपूर्ति मुंबई-अहमदाबाद हाईवे जैसी बहु-करोड़ परियोजनाओं और हिमालय क्षेत्र में बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (बी.आर.ओ.) की परियोजनाओं को बाधित कर सकती है। सन् 2020 की सीमा झड़पों के बाद चीन ने इन परियोजनाओं पर आपत्ति भी जताई थी। भारत ने भी चीन के इन कदमों के जवाब में उसके निवेशों पर रोक लगाई थी। अब चीन से आने वाले किसी भी निवेश को मंजूरी लेना आवश्यक है, जबकि अन्य देशों के साथ यह शर्त नहीं है। इन प्रतिबंधों के बाद चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट आई है।

दूसरी तरफ, भारत ने भी व्यापारिक कूटनीति के ज़रिए चीन को चोट पहुँचाने की कुछ कोशिशें की हैं, लेकिन ये प्रयास अभी भी कमजोर हैं, क्योंकि हम कई औद्योगिक इनपुट्स और आवश्यक सामग्रियों के लिए चीन पर निर्भर हैं।

लेकिन एक बात है, जिसे चीन को भी गंभीरता से लेना होगा। भारत बड़ा आयातक है, खासकर चीन के संदर्भ में,भारत, चीन से कुल 113 अरब डॉलर का आयात करता है, जबकि चीन हमसे केवल 14 अरब डॉलर का ही आयात करता है। यह व्यापारिक घाटा लगभग 100 अरब डॉलर का है, जो चीन के पक्ष में है। भारत द्वारा चीन से आयात और व्यापार घाटे की मांग कुछ कम नहीं है। अमेरिका का चीन के साथ लगभग 450 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है। हालाँकि, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है, फिर भी हम चीन की आर्थिक गतिविधि में अपेक्षाकृत काफी योगदान दे रहे हैं।

ईरान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आकलन के आधार पर दी। ईरान इंटरनेशनल के अनुसार, अगर इस कदम की पुष्टि हो गयी तो इसका मतलब होगा कि ईरान का 60 प्रतिशत शुद्धता वाला समृद्ध यूरेनियम का 408 किलोग्राम का अधिकांश भंडार सुरक्षित है। हांलाकि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने इसे नष्ट करने का दावा किया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने यूरोपीय संघ के अधिकारियों के हवाले से कहा कि जिस समय हमला हुआ, उस समय ईरान का भंडार संभवत: अलग-अलग जगहों पर था। एक प्रारंभिक खुफिया रिपोर्ट में बताया गया कि क़ोम के निकट भूमिगत फ़ोर्डो सुविधा में व्यापक क्षति हुई है, लेकिन पूरा विध्वंस नहीं हुआ। ईयू के अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की परमाणु क्षमताओं की वर्तमान स्थिति के बारे में यूरोपीय सहयोगियों को निश्चित खुफिया जानकारी नहीं दी है।

पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा का धूमधाम से शुभारंभ हुआ

पुरी, 27 जून। ओडिशा में पुरी स्थित विश्वप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के पीठासीन देवताओं, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का नौ दिवसीय प्रवास आज सुबह 'हरिबोल' और 'जय जगन्नाथ' के जयघोष और मंदिर नगरी में मंजीरों की लयबद्ध झंकार के बीच शुरू हुआ।

दुनियाभर में विख्यात इस वार्षिक रथ यात्रा को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु इस तीर्थ नगरी में आए हुए हैं। वे 12वीं शताब्दी के मंदिर के 'लायंस गेट' से गुंडिचा मंदिर तक फैले तीन किलोमीटर लंबे बड़ा डांडा (विशाल मार्ग) ग्रैंड रोड पर एकत्रित हुए। दैनिक अनुष्ठान पूरा होने के बाद सबसे पहले भगवान सुदर्शन के साथ दैवीय रूपों वाले भाई-बहनों को गोपाल भोग (नाश्ता) अर्पित किया गया। इसके बाद उन्हें भव्य जुलूस के रूप में गर्भगृह (रत्न वेदी) से बाहर लाया गया, जिसे पहांडी बिजे के नाम से जाना जाता है। फिर उन्हें मंदिर के बाहर खड़े उनके सुसज्जित रथों तक ले जाया गया। सैकड़ों मंदिर सेवकों ने देवताओं को अपने कंधों पर उठाकर सिंह द्वार तक पहुंचाया।

SBI
भारतीय स्टेट बैंक
केन्द्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई
फोन: 022-22820427

परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती

भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारियों के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं.

रिक्तियों की संख्या : 541

पात्रता मानदंड (आयु, शैक्षणिक योग्यता, आदि), आवश्यक शुल्क, ऑनलाइन आवेदन करने एवं ऑनलाइन शुल्क भुगतान के लिए बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi/careers/current-openings** पर विज्ञापन क्र. **CRPD/PO/2025-26/04** के अंतर्गत लिंक उपलब्ध हैं. प्रत्याशियों को परामर्श दिया जाता है कि वे विस्तृत विज्ञापन देखें और आवेदन करने एवं शुल्क भुगतान करने से पहले अपने पात्रता मानदंडों और अन्य विवरणों को सुनिश्चित कर लें.

- **ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क के भुगतान की तिथि: 24.06.2025 से 14.07.2025**

किसी भी तरह की पुछताछ करने के लिए कृपया हमें **"CONTACT US"** लिंक के माध्यम से हमें लिखें, जो ऊपर उल्लिखित बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.

स्थान: मुंबई
दिनांक: 24.06.2025 **महाप्रबंधक (आरपी एंड पीएम)**

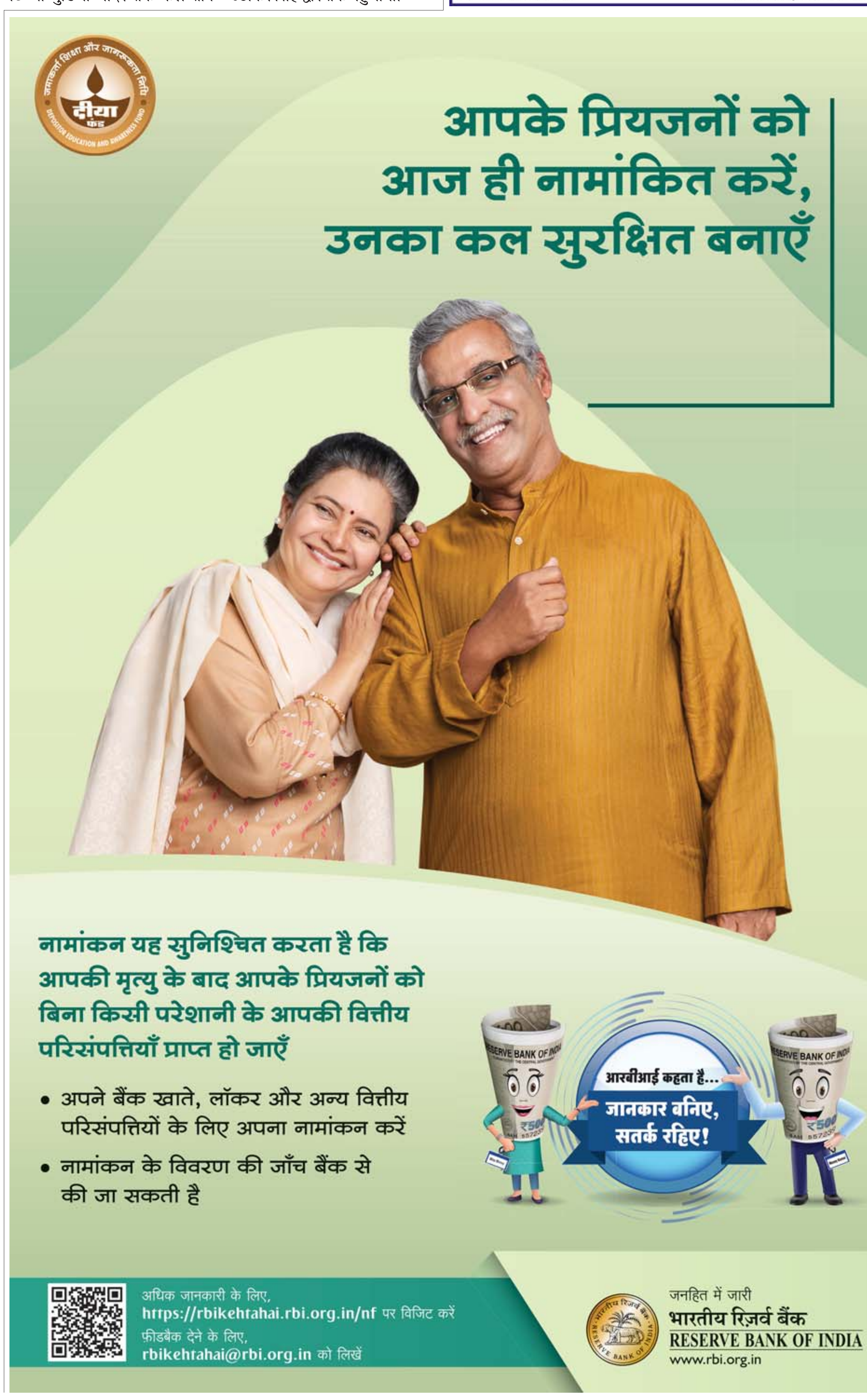

'केवल भाषणबाजी, इच्छाशक्ति व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि संघर्ष विराम की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया या नहीं। जब दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर अड़े हों, तो संवाद की राह और संकरी हो जाती है।

ट्रंप की टिप्पणियों से यह भी स्पष्ट हो गया कि अब वॉशिंगटन युद्ध का भार अकेले उठाने को तैयार नहीं है। उन्होंने दोहराया कि अमेरिका सैन्य सहायता (संभवत: पैट्रियट मिसाइल सिस्टम) देना जारी रखेगा, लेकिन अब यूरोपीय सहयोगियों को कहीं बड़ी भूमिका निभानी होगी। शिखर सम्मेलन में नाटो सदस्यों ने अपने रक्षा खर्च को जीडीपी के 5 प्रतिशत तक बढ़ाने पर सहमति जताई, यह ऐसा लक्ष्य है, जिसे ट्रंप ने लंबे समय से ज़रूरी बताया है। संदेश साफ था, यूरोप अब अमेरिकी मदद को असीमित सुरक्षा गारंटी न माने।

हालाँकि रूस के साथ वार्ता शुरु करने के प्रयास जारी हैं पर ट्रंप ने माना कि रूस ने अब तक केवल सीमित संघर्ष विराम की बात की है, वह भी अस्वीकार्य क्षेत्रीय मांगों के साथ। उनके प्रशासन की कूटनीतिक कोशिशों से कीव और यूरोपीय देशों में चिंता बढ़ी है, जो जोर देते हैं कि किसी भी समाधान में यूक्रेन की पूरी भागीदारी होनी चाहिए। ''यूक्रेन के बारे में बिना यूक्रेन के कुछ नहीं,'' यह वाक्य अब एक स्पष्ट कूटनीतिक लक्ष्मण रेखा बन चुका है, और ट्रंप इसका उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं।

इस बीच, नाटो का रूस के प्रति रवैया भी कुछ नरम हुआ है। जहाँ एक ओर गठबंधन ने सामूहिक सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और रूस को दीर्घकालिक खतरा बताया, वहीं इस वर्ष के सम्मेलन में क्रेमलिन की आलोचना अपेक्षाकृत कम थी। यूक्रेन की आवाज़ भी पहले से धीमी रही, क्योंकि ध्यान अब बजट लक्ष्यों और ईरानी आक्रामकता जैसे अन्य भू-राजनीतिक मुद्दों पर केन्द्रित रहा

सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इन बदलते समीकरणों ने पश्चिमी रणनीति की पुनर्समीक्षा शुरू कर दी है। ट्रंप के करीबी हलकों में यह चिंता बढ़ रही है कि रूस पर और प्रतिबंध लगाना उल्टा असर डाल सकता है। इससे क्रेमलिन पर दबाव तो बढ़ेगा, लेकिन साथ ही कूटनीतिक रास्ते भी बंद हो सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''हम दबाव बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चाहते कि सारे कूटनीतिक दरवाज़े ही बंद हो जाएं।''

ट्रंप के बयान उनके चुनावी भाषणों की निश्चितता से बिल्कुल उलट थे। अब वे खुद स्वीकार कर रहे हैं कि यह युद्ध कहीं ज़्यादा जटिल, अस्पष्ट और किसी एक नेता के नियंत्रण से बाहर है। यूक्रेन का युद्ध रातों-रात समाप्त नहीं होगा, और लंबे समय बाद पहली बार, ट्रंप ने यह बात स्वयं कही है।

भारत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कुल 4415 भारतीय नागरिकों (ईरान से 3597 और इज़राइल से 818) को भारतीय वायुसेना के तीन विमानों सहित 19 विशेष निकासी उड़ानों के माध्यम से निकाला गया है। इनमें 14 ओसीआई कार्ड धारक, 09 नेपाली नागरिक, 04 श्रीलंकाई नागरिक और एक भारतीय नागरिक के एक ईरानी जीवनसाथी को भी ईरान से निकाला गया।

एससीओ में भारत का अकेला पड़ना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का कहना है कि एससीओ में भारत के प्रभाव की भारी कमी विदेश नीति की व्यापक विफलता का संकेत है।

पूर्व भारतीय राजनयिकों ने, नाम न छापने की शर्त पर, खुलकर अपनी राय रखी। एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा, ''शंघाई सहयोग संगठन कोई साधारण बहुपक्षीय क्लब नहीं है। यह एशिया में शक्ति संतुलन में हो रहे बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, और इस मंच पर भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन रणनीतिक दिशा की स्पष्टता के अभाव में, अब यह उपस्थिति केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई है।''

इस आलोचना के केन्द्र में विदेश मंत्री एस. जयशंकर का काम-काज है। शुरुआत में उन्हें वैश्विक मामलों की गहरी समझ रखने वाले एक अनुभवी टैक्नोक्रैट एवं राजनयिक के रूप में सराहा गया था, लेकिन अब उनके कार्यकाल पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। आलोचकों का कहना है कि जयशंकर, भारत के रणनीतिक हितों के रक्षक के बजाय, सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधारा के प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनका आक्रामक लहजा और बार-बार की राष्ट्रवादी भाषणबाजी, जो देश में भले ही लोकप्रिय हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे न तो कोई सहयोग मिलने की स्थिति बनी, और न ही विरोधियों का रवैया बदला। कई विदेश नीति विशेषज्ञों का मानना है कि जयशंकर का कार्यकाल प्रतिक्रियाशील रवैये के लिये ज्यादा पहचाना गया है, न कि सक्रिय कूटनीति के लिये। जाने -माने भू-राजनैतिक विश्लेषक प्रोफेसर राजन मेनन ने कहा, ''चाहे वह पश्चिम एशिया में भारत का प्रभावहीन होना हो, चीन नीति को लेकर भ्रम एवं असमंजस की स्थिति हो, या रूस और अमेरिका के बीच संतुलन साधने में असफलता, विदेश मंत्रालय की कोई स्पष्ट वैश्विक दृष्टि एवं सोच नज़र नहीं आती।'' हालांकि, केवल जयशंकर को दोष देना अधूरी सोच होगी। बड़ी विफलता तो शीर्ष स्तर पर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विदेश नीति के सम्बंध में निर्णय लेने का काम अपने कार्यालय में केन्द्रित कर दिया है। पीएम की प्राथमिकता दिखावटी कूटनीति पर रही है- भव्य शिखर सम्मेलन, विश्व नेताओं के साथ फोटो खिंचवाना और प्रवासी भारतीयों की विशाल सभाएं और उनके लिए बड़े-बड़े आयोजन, लेकिन ये सब स्थायी भू-राजनीतिक लाभ में नहीं बदले। कभी वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज़ बुलंद करने का वादा करने वाली मोदी की विदेश नीति इन दिनों बिल्कुल भिन्न वास्तविकता सामने ला रही है। भारत अलग-थलग पड़ता जा रहा है, चाहे वह जलवायु परिवर्तन का बिन्दु हो, क्षेत्रीय संघर्ष हो या बहुपक्षीय संस्थाएं। इस तरह से अलग -थलग पड़ना विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि वैश्विक शक्ति समीकरण तेजी से बदल रहे हैं।

एशियाई सुरक्षा ढांचे में चीन प्रमुख भूमिका निभा रहा है, और रूस भी, पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद, अपना प्रभाव पुन: स्थापित कर रहा है। ऐसे में, भारत की रणनीतिक अस्पष्टता ने इसे सहयोगियों और विरोधियों, दोनों की नज़रों में अविश्वसनीय बना दिया है। यहां तक कि ईरान और मध्य एशियाई गणराज्य जैसे पारंपरिक सहयोगी देश भी अब चीन के प्रभाव क्षेत्र की ओर बढ़ते दिख रहे हैं, जिससे भारत की रणनीतिक स्थिति और कमजोर हो रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध या ईरान-इज़रायल संकट जैसे मुद्दों पर भारत की स्थिति स्पष्ट न होना - अक्सर मौन रहना या मतदान से परहेज करना- उसकी रणनीतिक अनिर्णय की छवि को और गहरा करता है। एससीओ शिखर सम्मेलन में भी यही अस्पष्टता की स्थिति एक बार फिर दिखाई दी। जहाँ अन्य देश स्पष्ट रुख अपनाते दिखे, भारत की ओर से हस्तक्षेप सतही रहा और वह प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों को सम्बोधित नहीं कर सका। अब यह मांग उठ रही है कि पूरी विदेश नीति पर पुनर्विचार हो। कई लोगों का मानना है कि जयशंकर को पद से हटाना एक शुरुआती कदम हो सकता है, लेकिन अन्तिम नही। केवल इससे बात खत्म नहीं होगी। भारत को विदेश मंत्री के रुप में केवल नया चेहरा ही नहीं चाहिये, बल्कि विदेश नीति की रणनीति में व्यापक सुधार की ज़रूरत है। देश को अपनी गुटनिरपेक्षता की परंपरा में लौटते हुए सक्रिय भूमिका को अपनाना होगा, न कि उस भ्रमित अलगाववाद को, जिसे रणनीतिक स्वायत्तता के आवरण में छुपाया जाता है। दुनिया तेजी से पुनर्गठित हो रही है, और भारत एक मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। यदि सरकार मौजूदा दिशा को स्वीकार कर, उसमें सुधार नहीं करती, तो भविष्य में वैश्विक मंचों पर उसे निश्चित रुप से और भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी और देश की भू-राजनीतिक स्थिति पर इसका गम्भीर असर होगा।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908